As regards the retired officials of Industrial Finance Corporation of India (IFCI) they are not required to take permission from the Government for their re-employment.

(c) The functions of the sponsored companies/institutions are of a specialised nature and call for professional expertise for nurturing such institutions at appropriate levels. The selection is made, on merits by the Board of Directors/Governors, of the respective institutions. The question of adversely affecting the fortunes and opportunities of others in the ladder of promotion, therefore, does not arise.

एच० एन० रे समिति

@1765ङ. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री राम जेठमिलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उसके द्वारा संचालित संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन के संबंध में अध्ययन करने हेतु श्री एच० एन० रे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मुख्य-मुख्य मामले क्या है जिन पर सिफारिशें देने के लिए समिति से आग्रह किया गया है ; और

(ग) इस समय उक्त समिति के गठन के क्या कारण हैं और इसके द्वारा सरकार को कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) 6-4-1992 को जारी किए गए आदेशों की प्रतिलिपि विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विचारार्थ विषय आदि दिए गए है ।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2092, 14 मई, 1992 से स्थानान्तरित ।

विवरण

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 6 अप्रैल, 1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 1(19)/91-संस्था० ii (ख) की प्रतिलिपि

सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा राष्ट्रीकृत बैंकों आदि में वेतन-ढांचे, अर्थात वेतन, मंहगाई भत्ता और स्वीकार्य अतिरिक्त लाभों सहित अन्य भत्तों का अध्ययन करने और उनकी जांच करने के साथ-साथ एक दस्तावेज तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिससे सरकार इन क्षेत्रों में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन प्रवृति की जांच करके महंगाई भत्ते की मंजूरी के लिए एक समान फार्मूला तैयार कर सके ।

2. विशेषज्ञ समिति का गठन निम्न प्रकार से है :–

(i) श्री एच० एन० रे अध्यक्ष

(ii) श्री वी० अटल सदस्य

(iii) श्री बी० स्वामिनाथन सदस्य

3. समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे :–

(i) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सांविधिक निगमों इत्यादि के कर्मचारियों के संबंध में मंहगाई भत्ते तथा वेतन का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों समेत मंहगाई भत्ते तथा वेतन ढांचे का अध्ययन करना ।

(ii) समान किस्म के पदों के लिए उनके सेवा कार्य में भिन्नता को उचित महत्व देते हुए केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि के कर्मचारियों की परिलब्धियों में अंतर का विश्लेषण करना ।

(iii) अध्ययन और जांच के आधार पर एक दस्तावेज तैयार करना जिस पर सरकार निम्नलिखित पहलुओं पर अपना दृष्टिकोण बना सके :–

(क) आर्थिक स्थिति तथा संसाधन की कठिनाइयों को मददेनजर रखते हुए वेतन पुनरीक्षण की प्रवृत्ति तथा केंद्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की परिलब्धियों के अंतर को कम करना ।

(ख) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सांविधिक निगमों इत्यादि के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न कर्मचारियों को उपलब्ध वेतन ढांचे, भत्तों सुविधाओं तथा सेवांत लाभों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता, मंजूर किए जाने के वास्ते एक समान फार्मूला तैयार करना ।

(ग) पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के सिद्धांत, नीती तथा फार्मूला बनाना ।

(घ) वेतन, महंगाई भत्ता और राहत के पुनरीक्षण की आवधिकता तय करना ।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति अपनी कार्यप्रणाली स्वंय तय करेगी तथा आवश्यक समझी जाने वाली सूचना मांग सकेगी ।

5. व्यय विभाग समिति के लिए सचिवालय उपलब्ध कराएगा ।

6. यह समिति 4 महीने की अवधि के अंदर वित्त मंत्रालय को दस्तावेज प्रस्तुत करेगी ।

ह०/–
(पी० जी० लेले)
अपर सचिव, भारत सरकार

Wind Power Generation in Tamil Nadu

$ @ 1766. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of POWER AND NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether any new wind power project has been sanctioned to Tamil Nadu other than Kayathar Kanyakumari and if so, the details thereof:

(b) whether Government are increasing the capacity at Kayattar for wind power energy;

(c) which are the other favourable locations in Tamil Nadu for establishing wind power energy generation; and

(d) what are the details of investigation and the feasibility studies made for Sea Waves power generation and when and where such station will be located?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir. The details of new wind power projects sanctioned to Tamil Nadu, other than Kayathar and Kanyakumari, are given below:

$ @ Previously unstarred Question 1295, transferred from the 7th May, 1992.